

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
परिवहन विभाग
5/9, अण्डर हिल रोड, दिल्ली - 110054

सं. एफ 19(04)/परि०वि०/सचि० शा०/2019/123624

दिनांक : 31/12/2021

सेवा में,

उप-सचिव (प्रश्न),

दिल्ली विधान सभा सचिवालय,

पुराना सचिवालय, दिल्ली - 110054

बिषय :- दिनांक 03/01/2022 को सदन की बैठक में लिए जाने वाले अतांराकित प्रश्न संख्या 11

महोदय,

आपके पत्र के संदर्भ में उपरोक्त प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियाँ संलग्न है।

यह माननीय परिवहन मंत्री के पूर्व अनुमोदन से जारी हुआ है।



(विकास जैन)

पीसीओ (सचि०)

VIKAS JAIN

Pollution Control Officer

Transport Department

5/9, Under Hill Road, Delhi-54

विभाग का नाम — परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार
विभाग का पता — 5/9, अंडर हिल रोड, दिल्ली — 110054
अतारांकित प्रश्न संख्या — 11
सदस्य का नाम — श्री विजेन्द्र गुप्ता
दिनांक — 03.01.2022

क्या माननीय परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि दिल्ली परिवहन निगम की सभी लगभग 3700 बसें जो सड़क पर हैं, ये बसें अपनी निर्धारित तकनीकी आयु 12 वर्ष या 7.50 लाख किलोमीटर पूरी कर चुकी हैं;	जी नहीं। लो फ्लोर सी एन जी बसों की निर्धारित आयु पंजीकरण तिथि से 15 वर्ष है।
ख	क्या यह भी सत्य है कि 15 वर्षों से डीटीसी के बेड़े में एक भी नई बस नहीं जोड़ी गई है;	वर्ष 2008 के निविदा द्वारा 3125 लो फ्लोर सी एन जी एसी व Non AC बसें खरीदी गई, जिनकी आपूर्ति वर्ष 2011 तक हुई। इसके पश्चात मार्च 2013 में 500 Non AC और 125 एसी लो फ्लोर सीएनजी बसों को 7,50,000 किलोमीटर तक की एएमसी सहित खरीदने हेतु निविदा प्रकाशित की गई। जिसमें 125 एसी बसों के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं हुई, तथा 500 Non AC बसों की सिंगल बोली प्राप्त हुई। बसों (मुल्य रु 75,97,991/- प्रति बस) और उनकी AMC (प्रथम वर्ष दर रु 83.06/- से 12वे वर्ष दर रु 433.08/-प्रति किलोमीटर) के हाई अनरीजनेबल रेट्स के कारण यह निविदा रद्द कर दी गई। अक्टूबर 2013 में 1380 Non AC स्टैण्डर्ड 900 MM फ्लोर हाईट और 345 प्रीमियम एसी लो फ्लोर सीएनजी बसों को 7,50,000 किलोमीटर तक की AMC सहित खरीदने हेतु निविदा प्रकाशित की गई। जिसमें 345 प्रीमियम एसी बसों के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं हुई, तथा 1380 Non AC स्टैण्डर्ड 900 MM फ्लोर हाईट बसों की सिंगल बोली प्राप्त हुई। Conditional तकनीकी बोली के कारण यह निविदा रद्द कर दी गई। तत्पश्चात जून 2014 में 1380 Non AC स्टैण्डर्ड 900

		एमएम फ्लोर हाईट सीएनजी बसों को 6,50,000 किलोमीटर तक की AMC सहित खरीदने हेतु निविदा प्रकाशित की गई, जिसमें बसों के लिए सिंगल बोली प्राप्त हुई, बसों (मूल्य रु. 44,63,753/- प्रति बस) और उनकी AMC (प्रथम वर्ष दर रु. 32.12/- से 10वें वर्ष दर रु. 104.98/-प्रति किलोमीटर) के हाई अनरिजनेबल रेट्स के कारण यह निविदा रद्द कर दी गई। मार्च 2018 में 1000 Non-AC स्टैंडर्ड 900 MM फ्लोर हाईट सीएनजी बसों को बिना AMC के खरीदने हेतु निविदा प्रकाशित की गई। निपुन मलहोत्रा बनाम दिल्ली सरकार वाले केस में दिल्ली परिवहन निगम द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार केवल लो फ्लोर सीएनजी बस खरीदने के लिए शपथ पत्र दाखिल कर दिया गया। जिसके पश्चात 1000 बसों के लिए सिंगल बोली प्राप्त होने के कारण यह निविदा रद्द कर दी गई। दिल्ली सरकार के केबिनेट निर्णय न. 2713 दिनांक 11.07.2019 के अनुसार जुलाई 2019 में 1000 एसी लो फ्लोर सीएनजी बसों को खरीदने व सितम्बर 2019 में उनके 7,50,000 किलोमीटर तक की AMC हेतु अलग अलग निविदाएं प्रकाशित की गई। जिसमें 1000 AC बसों व AMC के लिए अलग अलग दो बोलियां प्राप्त हुई। तकनीकी खामियों के कारण यह निविदाएं रद्द कर दी गई। तदोपरान्त उपरोक्त केबिनेट निर्णय के अनुसार मार्च 2020 में 1000 नई बीएस- VI एसी लो फ्लोर सीएनजी बसों को खरीदने व अगस्त 2020 में उनके 7,50,000 किलोमीटर तक की AMC हेतु अलग अलग निविदाएं प्रकाशित की गई। जिसमें 1000 नई बीएस-VI एसी बसों व एएमसी के लिए अलग अलग दो बोलियां प्राप्त हुई। दिनांक 15.01.2021 को 1000 नई बीएस- VI एसी लो फ्लोर सीएनजी बसों की सप्लाई एवं दिनांक 29.01.2021/01.02.2021 को उनकी एएमसी के लिए बस निर्माताओं को आर्डर दे दिया था, परन्तु 12.03.2021 को नेता प्रति पक्ष मान्नीय विधायक श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी व अन्य सात मान्नीय विधान सभा सदस्यों (श्री मोहन सिंह बिष्ट, श्री विजेन्द्र गुप्ता, श्री अजय महावर, श्री ओम
--	--	--


ASHISH KUNDRA, IAS
 Pr. Secretary-Cum-Commissioner (Tpt)
 Transport Department,
 CMCT of Delhi
 5/9, Under Bldg No. 3, Connaught Place, New Delhi-110054

	प्रकाश शर्मा, श्री अनिल वाजपेयी, श्री अभय वर्मा व श्री जितेन्द्र कुमार महाजन) द्वारा माननीय उप राज्यपाल को लिखित की गई शिकायत के कारण दिल्ली परिवहन विभाग के दिनांक 11.06.2021 के निर्देशानुसार 1000 बसों की खरीद व उनके AMC अनुबंध को अगले आदेश तक स्थगित रखा गया है। (Kept in Abeyance) उपरोक्त शिकायत की जांच के लिए माननीय उपराज्यपाल द्वारा दिनांक-16.06.2021 के आदेशानुसार एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट माननीय उपराज्यपाल को सौंप दी है। बसों की खरीद व उसकी AMC के मामले की जांच जारी है। इसके अतिरिक्त यह सूचित किया जाता है कि भारत सरकार की फेम-2 योजना के अंतर्गत दिल्ली परिवहन निगम ने 30.03.2021 को 300 नई एसी लो फ्लोर इलेक्ट्रिक Electric बसों को 10 साल के लिए ओपेक्स (Opex) मॉडल में परिचालन करने के लिए बस निर्माताओं को आर्डर दे दिया है, जिसमें मेसर्स जे.बी.एम (एल-1) को 200 और मेसर्स टाटा मोटर्स को 100 बसों का आर्डर प्रथम वर्ष के लिए 68.58 रु प्रति किलोमीटर की दर से दे दिया है, उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष यह दर अनुबंध की शर्तों के अनुसार निर्धारित होगा। एक प्रोटो टाइप इलेक्ट्रिक बस डीटीसी ने प्राप्त कर ली है और सभी 300 इलेक्ट्रिक बसें शीघ्र ही डीटीसी के बेड़े में शामिल हो जाएंगी। भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries, Govt. of India) की Grand Challenge योजना के अन्तर्गत दिल्ली परिवहन निगम 1500 इलेक्ट्रिक वातानुकूलित लो फ्लोर बसों को लेने की प्रक्रिया पर कार्यरत है। दिल्ली सरकार की क्लस्टर मॉडल में सन् 2015 से 1789 सीएनजी बसें (1386 Non AC तथा 403 AC) जोड़ी गई हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार ने क्लस्टर मॉडल के अन्तर्गत 1000 इलेक्ट्रिक वातानुकूलित लो फ्लोर बसों को जोड़ने का निर्णय लिया है। इसके अन्तर्गत प्रथम चरण में 330 बसों की निविदा जारी कर दी गई है।
--	--

ग	क्या यह सत्य है कि इस वर्ष के प्रारंभ में 1000 डीटीसी की पुरानी बसें जिनकी आयु पूरी हो चुकी है, उनको सड़कों पर चलाये रखने के लिए एक कंपनी से अनुबंध किया गया है जिस पर 500 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं;	जी नहीं। हालांकि 12 साल (7,50,000 किलोमीटर) की AMC समाप्त होने के पश्चात पारदर्शित प्रक्रिया के अनुसार 15 साल आयु के लिए 1000 (900 नान एसी व 100 एसी) बसों के आगे के रखरखाव के लिए ओपन टेण्डरींग प्रक्रिया द्वारा AMC को बढ़ाया गया है, जिसके लिए प्रति किलोमीटर दर के अनुसार भुगतान होगा।
घ	यदि हाँ, तो अगर डीटीसी बेड़े की सभी 3728 बसों को बदलने का तय करें तो कुल 1800 करोड़ रुपये खर्च आयेगा जिसकी तुलना में पुरानी बसों के रखरखाव के लिए इससे ज्यादा राशि दिल्ली सरकार द्वारा खर्च किए जाने के क्या कारण हैं;	उपरोक्त अनुसार।
ङ	क्या यह सत्य है कि वर्ष 2015 से हर साल डीटीसी को लगातार घाटा हो रहा है; और ...	जी नहीं, निगम की किराया संरचना सामाजिक दायित्वों पर समाज के विभिन्न वर्गों के लिये कई तरह के रियायती भुगतान जारी करने व मानव/सामग्री इनपुट लागत की कीमतों में वृद्धि के कारण जो भी नुकसान होता है वह दिल्ली सरकार द्वारा अनुदान राशि के रूप में दिल्ली परिवहन निगम को उपलब्ध कराई जाती है।
च	डीटीसी का घाटा लगातार बढ़ने तथा दिल्ली में बसों की संख्या लगातार घटने पर भी पिछले सात सालों में दिल्ली सरकार द्वारा एक भी नई बस को दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में न जोड़े जाने के क्या कारण हैं?	उपरोक्त (ख) के अनुसार।



(आशीष कुन्द्रा)
प्रमुख सचिव सह आयुक्त (परिवहन)
विभागाध्यक्ष

ASHISH KUNDRA, IAS
Pr. Secretary-Cum-Commissioner (Tpt)
Transport Department,
GNCT of Delhi
5/9, Under Hill Road, Delhi-110054